

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं उग्र राष्ट्रवाद: एक सिंहावलोकन

डॉ० सुशील कुमार

राघोपुर, सुपौल (बिहार), G-mail- gspusushil95@gmail.com

Paper Received On: 21 FEBRUARY 2026

Peer Reviewed On: 25 MARCH 2026

Published On: 01 APRIL 2026

Abstract

कांग्रेस की अनुनय विनय की नीति से ब्रिटिश सरकार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ सका। इसके प्रतिक्रियास्वरूप इस भावना का जन्म हुआ कि स्वराज्य मांगने से नहीं अपितु संघर्ष से प्राप्त होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पुराने नेताओं के संवैधानिक आंदोलन, आदर्श तथा उनके कार्य शैली से भारतीयों में विश्वास उठता चला गया। अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की जिस भावना का जन्म हुआ; वह 'उग्रराष्ट्रवाद' की भावना कहलाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक दल इसी भावना के कट्टर समर्थक थे। जिनका विचार था कि कांग्रेस का ध्येय स्वराज्य होना चाहिए; जिसे वे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से प्राप्त करें। यह दल उग्रवादी कहलाया।¹

M.R. Palande ने लिखा था कि उदारवादी अपनी राजनीति की व्याख्या 'उदारवाद और संयम' के समन्वय से करते थे। ये लोग भारतीयों के लिए धर्म और जाति के पक्षपात का अभाव, मानव में समानता, कानून के सामने बराबरी, नागरिक स्वतंत्रताओं का प्रसार और प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की इच्छा करते थे। उनके ढंगों के विषय में महादेव गोविन्द रानाडे ने लिखा था कि, 'संयम का अर्थ यह है की उस वस्तु की अथवा उन आदेशों की झूठी आशा ही मत करो जो मिलनी असंभव हैं, अपितु समीपतम वस्तु की ओर समझौते और न्यासंगत भावना से प्रेरित होकर दिन-प्रतिदिन आगे बढ़ते जाओ।'²

उग्रवादियों ने बीसवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में उदारवादियों की उपलब्धियों की निंदा की तथा इसकी अनुनय-विनय की नीति को 'राजनितिक भिक्षावृत्ति' का नाम दिया। लाला लाजपत राय ने इसको 'अवसरवादी आंदोलन' की संज्ञा दी। अधिक से अधिक इससे पाखंड और देशद्रोह को बढ़ावा मिला है। कुछ लोगों को देशभक्ति के नाम पर व्यापार करने का अवसर मिला।³

उदारवादी राष्ट्रवादियों ने भारतीय राजनीति को एक नया रूप प्रदान किया। देश में नयी राजनीतिक चेतना जगाई और बुद्धिजीवियों तथा मध्यवर्गीय लोगों को उनके सामूहिक हितों तथा राष्ट्रियता के प्रति सचेत किया; उपनिवेशवाद की आर्थिक अवधारणा व उसके चरित्र को जनता के सामने उजागर किया; राजनीतिक कला का प्रशिक्षण दिया और पहली बार भारतीय जनता को लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा नागरिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया। उदारवादी नेताओं ने भारतीय जनता को संगठित करने व औपनिवेशिक हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए सामूहिक राजनीतिक-आर्थिक कार्यक्रम बनाए। बाद में इन्हीं नीतियों एवं कार्यक्रमों को लेकर राष्ट्रवादी संघर्ष छिड़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इन नेताओं ने एक ऐसे संगठन को जन्म दिया, जो बाद में सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन का रहनुमा बना।⁴

मुख्य शब्दः— उग्रवादी, उदारवादी, क्षमायाचना, प्लेग, स्वराज्य, बंगाल-विभाजन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट की प्रक्रिया लोकमान्य तिलक का समाज सुधार के प्रश्न पर 'उग्रवादी दल अथवा सुधारकों' से झगड़ा के साथ आरंभ हुई। तिलक और उसके सहयोगियों ने जुलाई 1895 ई० में पूना सार्वजनिक सभा में रानाडे और गोखले के अधिकार को चुनौती देकर समाप्त कर दिया तत्पश्चात् गोखले ने एक और पृथक राजनीतिक संगठन 'दक्कन सभा' स्थापित कर ली। तिलक ने गोखले के राष्ट्रीय राजनीति में 'क्षमा याचना' के प्रश्न पर 'एक कच्चा नरकट' कहकर बदनाम किया। क्षमा याचना के संदर्भ में गोखले द्वारा लंदन में मैनचेस्टर गार्डियन को लिखे पत्र का विवरण इस प्रकार है— 'उन्होंने प्लेग अफसरों की निंदा की थी तथा इसी विषय पर लंदन में एक भाषण भी दिया था। भारत सरकार ने उन आरोपों की जांच का आदेश दिया और गोखले को उसके समर्थन में तथ्य प्रस्तुत करने को कहा। गोखले ने जब उसकी स्वयं जांच की तो पता लगा कि वह सत्य नहीं थे और उन्होंने क्षमा याचना की और कहा कि उन्हें समाचार ठीक-ठीक नहीं मिला था। तिलक सरकार की आलोचना में बहुत स्पष्ट वक्ता थे और अपने विश्वासों के लिए बलिदान करने को हमेशा उद्धृत रहते थे। वह पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल यात्रा की। दिसंबर 1897 में अमरावती में संपन्न हुए कांग्रेस अधिवेशन में तिलक के सहयोगियों ने 'तिलक की मुक्ति' की मांग का प्रस्ताव पारित करवाने का प्रयत्न किया, परंतु उदारवादी दल ने इसकी अनुमति नहीं दी। मद्रास अधिवेशन (दिसंबर 1893) में तिलक की प्रस्ताव तथा लखनऊ अधिवेशन बम्बई के गवर्नर की निंदा प्रस्ताव को उदारवादी दलों ने पारित नहीं होने दिया। उदारवादी दल वाले लोग तिलक और उसके सहयोगियों को कांग्रेस में सभी महत्वपूर्ण पदों से वंचित रखना चाहते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में तिलक को कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का अवसर नहीं दिया गया।⁵

'अरविंद घोष' ने लिखा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी है और यह पूर्णतया असफल रही है और इसकी शासकों को प्रसन्न करने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को 'कायरता' की संज्ञा दी। उसके अनुसार, कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते हुए कहा था कि "कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ" हैं। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलनों को "शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला" कहा।⁶

उग्रवादी दल, कांग्रेस के पहले 15-20 वर्ष की उपलब्धियों से असंतुष्ट थे। उनका अंग्रेजों की न्यायप्रियता तथा बराबरी की भावना पर कोई विश्वास नहीं रह गया था। वे लोग शांतिमय और संवैधानिक ढंगों के आलोचक बन गए थे तथा उनका मानना था कि याचना, प्रार्थना तथा प्रतिवाद (Patition, Prayer and Protest) करने की नीति से कुछ नहीं मिलने वाला है। उग्रवादियों ने यूरोपीय साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए यूरोपीय ढंग ही अपनाए पर बल दिया। 1905 में लाला लाजपत राय ने इंग्लैंड से लौटने पर अपने देशवासियों को यह बतलाया कि अंग्रेजी प्रजातंत्र अपनी ही समस्याओं में इतना उलझा हुआ है कि उनके पास हमारी समस्याओं के लिए समय नहीं। वहां के

समाचार पत्र हमारा पक्ष प्रस्तुत नहीं करेंगे और वहां किसी को अपनी बात सुनाने का अवसर प्राप्त करना बहुत कठिन है। उन्होंने कहा कि यदि आप स्वतंत्रता चाहते हैं तो स्वयं कार्य करना पड़ेगा और अपने तत्परता के स्पष्ट प्रमाण देने होंगे।⁷

राष्ट्रवादी उग्रवादी दल के अनुसार कांग्रेस का राजनीतिक धर्म, केवल क्रॉउन के प्रति राजभक्ति प्रकट करना; उद्देश्य केवल अपने लिए प्रांतीय अथवा केंद्रीय विधान परिषदों में सदस्यता प्राप्त करना और कार्यक्रम केवल अत्यधिक भाषण देना और प्रत्येक वर्ष के दिसंबर मास में कांग्रेस के अधिवेशन में उपस्थित होना था। उग्रवादियों ने दोष लगाया कि उदारवादी केवल मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवियों के लिए काम करते हैं और कांग्रेस की सदस्यता इन मध्यमवर्गीय लोगों तक ही सीमित है। उन्हें भय है कि यदि जनसाधारण इस आंदोलन में आ जाए तो उनका नेतृत्व समाप्त हो जाएगा। उदारवादी दल वालों को देश भक्ति के नाम पर व्यापार करने का दोषी ठहराया गया। तिलक ने कांग्रेस को 'चापलूसों का सम्मेलन' और 'कांग्रेस के अधिवेशनों को छुट्टियों का मनोरंजन' बतलाया। उग्रराष्ट्रवादी नेता तिलक ने तो यहां तक कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की भांति टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा।⁸

दादा भाई नौरोजी *India Poverty and UnBritish Rule in India* (1901) रानाडे की *Essays in India Economics* और R.C. Datt की *Economics History of India* (1901) इत्यादि पुस्तकों ने अंग्रेजी राज्य की सही स्वरूप एवं उनकी शोषक नीतियों का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दादाभाई नरोजी ने अंग्रेजी राज्य की शोषक नीतियों का अनावरण करते हुए कहा कि ब्रिटिश राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में रत हैं तथा इनकी शोषक नीतियां ही भारत की दरिद्रता का मूल कारण हैं। 'सुरेंद्रनाथ बनर्जी' ने कहा कि सेवाओं की भर्ती में अंग्रेजों की कथनी और करनी में बहुत अधिक अंतर हैं। भारत की बढ़ती हुई दरिद्रता के उत्तरदायी उन्होंने ब्रिटिशों की अदूरदर्शी भूमि कर नीति, भारत के औद्योगीकरण के प्रति उदासीनता, गृह शासन के बढ़ते हुए खर्च, भेदभावपूर्ण आयात तथा निर्यात की नीति, सैनिक और असैनिक पदों पर ऊंचे ऊंचे वेतन और भारतीयों को अच्छे पदों और सेवाओं से वंचित रखना बतलाया।⁹

भारत की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति ने भारतीय राष्ट्रीय प्रक्रिया में उग्रवाद के उदय में विशेष योगदान दिया। 1896-97 और 1899-1900 के भीषण अकाल और महाराष्ट्र के प्लेग से लाखों लोग मृत्यु ग्रस्त हो गए। तिलक ने कहा कि सरकारी अधिकारी कठोर और भ्रष्ट थे और सहायक के स्थान पर अधिक हानिकारक थे। उन्होंने कहा कि प्लेग हमारे लिए सरकारी प्रयत्नों से कम निर्दयी है।¹⁰ 1903 की कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में लाल मोहन घोष ने 1902 के दरबार का उल्लेख इस प्रकार किया, 'एक सरकार का निर्धन जनता पर भारी कर लगाकर एक बड़े भारी समारोह का मनाना जिसमें आतिशबाजी और भव्य दृश्यों पर रुपया व्यय किया जाए, जबकि लाखों लोग भूख से मर रहे हैं, इससे अधिक हृदयहीनता कुछ नहीं हो सकती।'¹¹

समकालीन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रभाव ने भी भारत में उग्र राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। 1896 में इथियोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय, ब्रिटिश सेनाओं को गंभीर क्षति पहुंचाने वाले बोअर युद्ध (1899–1902) एवं 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजय जैसी घटनाओं ने यूरोपीय अजेयता के मिथक को तोड़ दिया। जनता की भावनाओं को समाचार पत्र ने इस प्रकार व्यक्त किया: “जो कुछ एक एशियाई देश ने किया है वह दूसरे भी कर सकते हैं, यदि जापान, रूस की पिटाई कर सकता है तो भारत भी ब्रिटेन को उसी तरह पीट सकता है। आइए, हम अंग्रेजों को समुद्र में फेंक दें और विश्व की महान शक्तियों के बीच जापान के बराबर अपना स्थान ग्रहण करें।”¹²

नवीन राष्ट्रवादी नेताओं ने बढ़ते हुए पश्चिमीकरण पर गहरी चिंता व्यक्त की क्योंकि भारतीय चिंतन एवं समाज में पश्चिमी प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। इससे भारतीय संस्कृति के पाश्चात्य संस्कृति में विलीन होने का खतरा पैदा हो गया। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी एवं स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे विद्वानों ने भारतीय तथा वैदिक संस्कृति के प्रति लोगों में नया विश्वास पैदा किया तथा भारत की प्राचीन समृद्ध विरासत का गुणगान कर पश्चिमी संस्कृति की पोल खोल दी। इन्होंने भारत की प्राचीन सांस्कृतिक समृद्धि का बखान कर पाश्चात्य सर्वश्रेष्ठता के भ्रम को तोड़ दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि जिस समय यूरोपवासी असभ्यता तथा अज्ञान के गड्ढे में गिरे थे, वैदिक काल में भारत में एक उच्च सभ्यता, संस्कृति, दर्शन और धर्म का विकास हो रहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती का राजनीतिक संदेश था ‘भारत भारतीयों के लिए हैं’¹³

लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने भी उग्र राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। लॉर्ड कर्जन का भारत में 07 वर्ष का शासन “शिष्टमंडलो, भूलो तथा आयोगों (Missions, Omissions and Commissions)” के लिए प्रसिद्ध है। इसकी भारतीय जनमानस पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई। कर्जन ने भारत को एक राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया तथा कांग्रेस को ‘मन के उद्गार निकालने वाली संस्था’ की संज्ञा दी। उसने भारत विरोधी बयान दिए तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए कहा था, “सत्य का मान पश्चिम में अधिक था और पूर्व में ऐसा बहुत समय के पश्चात हुआ है।” उसके शासन के विभिन्न प्रतिक्रियावादी कानूनों यथा—कार्यालय गोपनीयता अधिनियम (1904), भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (1904), कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम (1899) इत्यादि से भारतीय खिन्न हो गए। संभवतः कर्जन का सबसे घृणित कार्य बंगाल को दो भागों अथवा बंगाल तथा पूर्वी बंगाल और असम में विभाजित करना था। यह कार्य बंगाल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध की उपेक्षा करके किया।¹⁴

राजीव अहीर ने लिखा है कि बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में जुझारू या उग्र विचारधारा वाले राष्ट्रवादियों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ, जिसने राजनीतिक कार्यों एवं आंदोलनों के लिए उग्र तरीके

अपनाने पर जोर दिया। इन जुझारू राष्ट्रवादियों में बंगाल के राज नारायण बोस, अश्वनी कुमार दत्त, अरविंद घोष तथा बिपिन चंद्र पाल; महाराष्ट्र के विष्णु शास्त्री चिपलुणकर, बाल गंगाधर तिलक एवं पंजाब के लाला लाजपत राय प्रमुख थे। इन उग्र विचारधारा के उत्थान में सबसे अधिक सहयोग तिलक ने दिया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में 'मराठा' एवं मराठी में 'केसरी' के माध्यम से भारतीयों को उग्र राष्ट्रवाद की शिक्षा दी और स्पष्ट रूप से कहा कि "आजादी बलिदान मांगती हैं।"¹⁵

उग्रवादियों के कार्यक्रम के अनुसार, विदेशी माल का बहिष्कार और स्वदेशी माल अंगीकार करना तथा राष्ट्रीय शिक्षा और सत्याग्रह पर भी बल दिया गया। लाला लाजपत राय के अनुसार स्वदेशी के प्रचार से अंग्रेजों को वित्तीय हानि होगी और बंगाल का विभाजन रद्द करने के लिए दबाव डाला जाएगा। उग्रवादियों ने स्वदेशी और विभाजन-विरोधी आंदोलन को जन-आंदोलन बनाने की कोशिश की और विदेशी शासन से मुक्ति का नारा दिया। अरविंद घोष ने खुलकर घोषणा की कि "राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु है।" वो स्वराज्य की प्राप्ति को भारत के प्राचीन जीवन का आधुनिक परिस्थितियों में परिपूर्ण होना और राष्ट्रीय गौरव का सतयुग मानते थे जिसमें भारत पुनः एक गुरु और मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका निभाए, लोगों की आत्म-मुक्ति हो ताकि राजनीतिक जीवन में वेदांत के आदर्श को प्राप्त कर सकें; यही भारत के लिए सच्चा स्वराज्य होगा।¹⁶

इतिहासकार बिपिन चंद्र ने लिखा है कि उग्र राष्ट्रवादी जनता को सकारात्मक नेतृत्व देने में असफल रहे। उन्होंने जनता को जागृत तो कर दिया मगर यह नहीं समझा सके की जनता इस नई-नई निकली शक्ति का उपयोग कैसे करें या राजनीतिक संघर्ष के नए रूप क्या हों। निष्क्रिय प्रतिरोध और असहयोग विचार मात्र बनकर रह गए। उग्रराष्ट्रवादी देश की वास्तविक जनता, अर्थात् किसानों तक पहुंचने में भी असफल रहे। उनका आंदोलन नगरों के निम्न और मध्य वर्गों तथा जमींदारी तक सीमित रहा। 1908 के अंत तक उनकी राजनीति एक बंद गली में समा चुकी थी। परिणामस्वरूप उन्हें दबाने में सरकार काफी हद तक सफल रही। उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेता तिलक की गिरफ्तारी का तथा बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष द्वारा सक्रिय राजनीति से सन्यास का धक्का नहीं झेल सके।¹⁷

उग्र राष्ट्रवादी अथवा गरम दल ने जनता को; असहयोग, अहिंसात्मक प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन, आत्मनिर्भरता और दुःख सहने का नया पाठ पढ़ाया। इन लोगों ने देशभक्ति को 'विद्या विनोद' से परिवर्तित कर 'देश सेवा तथा दुःख सहना' बना दिया। उग्रवादियों की नीति के कारण ही 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। स्वराज्य का उद्देश्य मोर्ले ने तो पूरा नहीं किया परंतु अब यह क्रांतिकारी मांग नहीं रह गई और प्रथम विश्वयुद्ध में सरकार ने यह घोषणा की कि 'भारतीय संवैधानिक सुधारों स्वशासन का उद्देश्य संस्थाएं स्थापित करना है।' भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का मूल्यांकन एक सक्रिय राजनीति के रूप में किया जाता है।

निष्कर्ष

संदर्भ ग्रंथ सूची :

- अहीर, राजीव : ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, *Sepctrum Books Pvt. Ltd.* -2024, पृ० 251
- पलांडे, एम.आर. (संस्करण): स्रोत— भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के लिए मीटरीअल वॉल्यूम-II, बाम्बे स्टेट कमिटी, पृ० 848, 49
- राय, लाजपत : यंग इंडिया, पृ० 156.
- चंद्र बिपिन, मुखर्जी मृदुला, मुखर्जी आदित्य, पणिक्कर के.एन., महाजन सुचेता : भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय, निदेशालय, दिल्ली, 2015, पृ० 94
- गोवर बी.एल., मेहता अलका, यशपाल : आधुनिक भारत का इतिहास, एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि०, नई दिल्ली, 2007, पृ० 303
- वही, पृ० 207
- राय, लाजपत : यंग इंडिया, पृ० 170.
- गोपाल राम : लोकमान्य तिलक, एशिया पब्लिशिंग हाउस, न्यूयार्क, 1965, पृ० 130.
- गोवर बी.एल., मेहता अलका, यशपाल : आधुनिक भारत का इतिहास, एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि०, नई दिल्ली, 2007, पृ० 304
- वही, पृ० 137
- कांग्रेस अध्यक्षीय भाषण (मद्रास) खंड-I, पृ० 62
- कराची क्रॉनिकल: 18 जून, 1905
- अहीर, राजीव : ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, *Sepctrum Books Pvt. Ltd.* 2024, पृ० 254
- बीसवीं कांग्रेस पर रिपोर्ट, 1904 संकल्प XIV
- अहीर, राजीव : ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, *Sepctrum Books Pvt. Ltd.* 2024, पृ० 255
- अरबिंदो: वंदे मातरम पत्रिका, 3 मई, 1908
- चंद्र, बिपिन : आधुनिक भारत का इतिहास, ऑरिएण्टल ब्लैकस्वान प्रा० लि०, नई दिल्ली, पृ० 207

Cite Your Article as

Dr. Sushil Kumar. (2026). BHARATIY RASHTRIY ANDOLAN EANV UGRA RASHTRAVAD: EK SINHAVALOKAN. Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language, 14(74), 229–234. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20083989>